दिल्ली दरबार में हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार

मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात

⇨ प्रदेशाध्यक्ष और प्रत्याशियों को लेकर मंथन

जगमार्ग ब्यूरो

चंडीगढ़। प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा में पिछले सप्ताह भर से बड़ी उठापठक के बीच अभी तक कैबिनेट विस्तार, पार्टी के नए अध्यक्ष और चार लोकसभा सीओं पर सहमति नहीं बन पा रही है। लिहाजा इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सोमवार को सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नई दिल्ली पहुंचे।

भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोनों ने मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष तथा हरियाणा मामलों के सह-प्रभारी सुरेंद्र नागर भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा होने की वजह से इस बैठक में नहीं पहुंच सके। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के दौरान हरियाणा से जुड़े इन तीनों ही मुद्दों पर फैसला हो चुका है। अभी तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं। पार्टी में एक व्यक्ति को दो पद देने की नीति नहीं है। ऐसे में सैनी की जगह नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाना है। बताते हैं कि प्रदेश में पार्टी के नये चेहरे के लिए कई नामों पर चर्चा हुई है। पार्टी पंजाबी, यादव, ब्राह्मण और एससी में से किसी वर्ग के नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाने पर कई दिनों से मंथन कर रही है। अब फाइनल चर्चा होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ा गया है। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी लटका हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं से हुई मुलाकात के दौरान सीएम और पूर्व सीएम ने कैबिनेट को लेकर भी विचार-विमर्श किया होगा। कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होने की उम्मीद है। दिल्ली दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की राज्यपाल बण्डारू दत्तात्रेय से भी मुलाकात हुई। ऐसे में कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं को और भी बल मिला है।

नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर पंजाबी, यादव, ब्राह्मण और एससी वर्ग पर नजर

माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश भाजपा को नया प्रधान मिल सकता है। पार्टी में पंजाबी कोटे से संजय भाटिया और मनीष ग्रोवर, ब्राह्मण से अजय गौड़ तथा एससी चेहरे के रूप में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार का नाम चर्चाओं में था। इसी तरह से पूर्व सांसद डॉ सुधा यादव का नाम भी भाजपा गलियारों में सुनने को मिला। बहरहाल, अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जल्द ही प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है।

विज से मुलाकात संभव

भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को सीएम नायब सैनी की पूर्व गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ मुलाकात हो सकती है। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दोनों के बीच मुलाकात नहीं हो पाया है। हालांकि 13 मार्च को विधानसभा में बहुमत प्रस्ताव के दौरान विज पहुंचे थे लेकिन दोनों के बीच वहां भी बातचीत नहीं हो पाई। सैनी के विज के अंबाला कैंट स्थित आवास पर जाने की संभावना है।

नायब सैनी ने सुनी सीएम आवास पर समस्याएं

मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी से सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने और फिर से एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीएम आवास पर समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश को निर्देश दिए।

चार टिकटों पर बना हुआ सस्पेंस

भाजपा लोकसभा की दस में से छह सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। चार संसदीय सीटों-कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक व सोनीपत के उम्मीदवारों को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। बताते हैं कि जातिगत समीकरणों की वजह से इन सीटों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। नई दिल्ली में हुई मीटिंग के दौरान चारों ही संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशियों को लेकर निर्णायक बातचीत होने की सूचना है। ऐसे में बहुत संभव है कि अब चारों सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा भी भाजपा जल्द ही कर दे।

हरियाणा में जेपी नड्डा आज करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद

जगमार्ग ब्यूरो

चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को करनाल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविन्द्र कल्याण, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव का आगाज करने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हरियाणा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में नड्डा मंगलवार को 11 बजे घरौंडा अनाज मंडी में करनाल लोकसभा के कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करेंगे।

मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव ने बताया कि मोदी सरकार ने 10 सालों में सकारात्मक बदलाव करते हुए देश और प्रदेश को विकास की गति पर तेजी से बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निर्णयों के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प होकर काम किया है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 सालों में ईमानदार प्रयास करते हुए हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे लेकर गए हैं।जवाहर यादव ने बताया कि दस सालों में मोदी सरकार की नीतियों के कारण गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आए हैं उनके बारे में कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो-जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है। जम्मू कश्मीर से धारा-370 हटाई है। उज्जवला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। गरीब परिवारों को पक्का मकान, हर घर नल से जल मोदी सरकार में संभव हो पाया है। जवाहर यादव ने कहा कि दस सालों में देश की सांस्कृतिक विकास विरासत और संस्कृति का उत्थान हुआ है। पूरे विश्व में मोदी के नेतृत्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। यादव ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा दस सालों में किए गए उल्लेखीय कार्यों और उपलब्धियों को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे।

जवाहर यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 सालों में हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन किया है। बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास किया और युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली हैं। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है।

दवा कंपनियां एंटीमैक्रोबिलय रेजिस्टेंस से निपटने के लिए खोजें वैक्सीन: बंडारू

जगमार्ग ब्यूरो

चंडीगढ़। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रमुख दवा कंपनियों से आहवान करते हुए कहा कि उन्हें एंटीमैक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के नए वर्गों और वैक्सीन विकास के वैकल्पिक तरीकों से नई दवाओं की खोज करनी होगी क्योंकि रोगाणुरोधी प्रतिरोध/एएमआर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती है तथा वर्तमान एंटीबायोटिक्स अब बेअसर हो रही हैं। राज्यपाल नई दिल्ली के इंडिया हैबीटेट सेंटर में ''एंटीमैक्रोबियल रेजिस्टेंस, नोवल ड्रग डिस्कवरी एंड वैक्सीन डेवलपमेंट- चैलेंजेज एंड ओपरचूनिटिस विषय पर एसआरएम विश्वविद्यालय, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत द्वारा आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित वैज्ञानिकों व साइंस जगत के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज यहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक उपस्थित हैं और अन्य वैज्ञानिकों के यहां पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एएमआर को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्यपाल ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि अनुमान है कि वर्ष 2050 तक दुनिया भर में लगभग दस मिलियन मौतें एएमआर के कारण हो सकती हैं।

दत्तात्रेय ने कहा कि एक नई दवा को बाज़ार में लाने पर लगभग एक अरब डॉलर का ख़र्च आता है और नए रोगाणुरोधी एजेंटों को विकसित करने के लिए नए यौगिकों की खोज, जीनोमिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों और अंत:विषय सहयोग को बढ़ावा देने जैसे नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि एएमआर ने प्रतिरोधी रोगजनकों से निपटने के लिए नवीन दवा खोज और वैक्सीन विकास की तत्काल आवश्यकता को प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए एंटीबायोटिक उपयोग को अनुकूलित करते हुए रोगाणुरोधी प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने, प्रतिरोधी रोगजनकों के प्रसार को कम करने के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों को लागू करने तथा विश्व स्तर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध रुझानों को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रणालियों में निवेश करना आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के अनुसंधान और विकास प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर रहा है।

राज्य में 1.48 लाख दिव्यांग मतदाता चुनेंगे पंसदीदा उम्मीदवार

चंडीगढ़ (जगमार्ग ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व लोकसभा चुनाव-2024 को मनाने के लिए चुनाव आयोग ने दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य में लगभग 1.48 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। अग्रवाल सोमवार को सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, रेड क्रॉस, लोक निर्माण इत्यादि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पोलिंग स्टेशनों पर किए जाने वाले प्रबंधों पर समीक्षा बैठक कर रहे थे।उन्होंने कहा कि उक्त श्रेणियों के मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर रैंप, व्हील चेयर, लाने व ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट इत्यादि की व्यवस्था करने के साथ-साथ एनसीसी एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों को उनकी सहायता के लिए तैनात किया जाए।

राजपूत समाज राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर करेगा मजबूत पैरवी: कुलदीप तंवर

जगमार्ग ब्यूरो

चंडीगढ़। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर मंत्रण हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि समाज में फैल रही कुरीतियों को समाप्त करने के साथ समाज के गरीब व असहाय लोगों के लिए राहत कोष बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए समाज के युवाओं को जोड़कर समाज में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही जनसंख्या के आधार पर राजनीति हिस्सेदारी की मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर मांग उठाई जाएगी। इसके साथ ही सममाज के गौरवशाली इतिहास पर दूसरे समाजों द्वारा फैलाई जा रही भ्रंतियों व भ्रामक प्रचारों का विरोध किया जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि फिल्मों और नाटकों के जरिये समाज का गलत चित्रण दिखाया जाता है, इसका भी विरोध किया जाएगा। इस अवसरपर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष शीशपाल सिंह, महामंत्री वीरेंद्र सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष दलबीर सिंह चौहान, युवा प्रधान राममेहर, महिला प्रधान प्रवेश राणा, यशवीर सिंह राणा, कर्नल देवेंद्र सिंह वीरचक्र और डॉ. एनपी सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

साइबर ठग सगे-संबंधियों को मेडिकल एमरजेंसी के नाम पर कर रहे ठगी

चंडीगढ़ (जगमार्ग ब्यूरो)। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि साइबर ठगों द्वारा कई बार लोगों के सगे संबंधियों को मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर पैसे की मांग की जाती है ताकि वे तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दे और इस तरह लोग घबरा कर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। डीजीपी ने बताया कि साइबर अपराध हम सभी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है लेकिन सर्तकता से बचा जा सकता है। आज के इस डिजिटल युग में लोग अधिक से अधिक ऑनलाइन माध्यम से पैसों का लेनदेन करते हैं और यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों का उल्लेख करते हुए बताया कि साइबर अपराधी लोगों के पास फोन करते हैं और उन्हें अलग-अलग प्रकार का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट से राशि अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं। कपूर ने स्पष्ट कहा कि आमजन को किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए लालच से अपना बचाव करना है और किसी भी व्यक्ति से ओटीपी शेयर नहीं करना है। उन्होंने कहा कि पैसा लेने के लिए कभी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि पैसा अकाउंट से बाहर निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है इसलिए लोग किसी भी प्रकार के लालच में ना पड़े।

निपुण एप पर 8.15 लाख विद्यार्थियों के वार्षिक आकलन का रिकार्ड दर्ज

⇨ अब 21 तक शिक्षकों के पास रिकार्ड दर्ज कराने का मौका

जगमार्ग ब्यूरो

चंडीगढ़। शिक्षकों के तबादले से निपुण हरियाणा टीचर एप पर कक्षा पहली से लेकर तीसरी तक के परीक्षा परिणाम का डाटा दर्ज कराने की गति धमी हो गई है। लिहाजा शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी मौलिक अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 21 मार्च तक एप पर डाटा दर्ज कराने की अवधि बढ़ाई गई है।

सोमवार तक निपुण हरियाणा टीचर एप पर 8 लाख 15 हजार विद्यार्थियों के वार्षिक आकलन का रिकार्ड शिक्षकों द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को कार्य की सराहा है। अध्यापकों के स्थानांतरण के चलते पहली से तीसरी कक्षा तक परीक्षा परिणाम का रिकार्ड दर्ज कराने की अवधि को 21 मार्च तक बढ़ाया गया है। बता दें कि 16 मार्च को कक्षा पहली से तीसरी तक की लिखित परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे में जो पुराने अध्यापक स्कूल से रिलीव हो चुके हैं या फिर उनका स्थानांतरण हो चुका है, वे अपने सभी परीक्षा परिणाम का रिकार्ड निर्धारित अवधि के भीतर एप पर अपलोड करें।

शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूल मुखियाओं को कड़ी हिदायत दी गई है कि निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा परिणाम एप पर अपलोड न होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पीआरटी अध्यापकों को स्कूल अलाट होने पर कार्यमुक्त करने करने के निर्देश

मौलिक शिक्षा निदेशक ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2017 में लगे पीआरटी अध्यापकों को स्कूल अलाट करने उपरांत कार्य मुक्ति च कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा अब 2017 बैच के अध्यापकों को आनलाइन स्कूल विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं, जिसकी प्रति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। निदेशालय की ओर से स्कूल मुखियाओं व अध्यापकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिले से संबंधित सभी जेबीटी अध्यापकों को तुरंत प्रभार से कार्यभार मुक्त व कार्य ग्रहण करें। निदेशालय की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अतिथि अध्यापक अपने वर्तमान स्कूल में कार्यरत रहेंगे, जब तक अतिथि अध्यापकों को विभाग द्वारा स्पेशल स्थानांतरण ड्राइव के माध्यम से स्कूल अलाट नहीं किए जाते हैं।

आईटीआई कर्मियों के सेवा विस्तार पर कमेटी करेगी फैसला

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार एवं बढ़ोतरी को तीन सदस्यीय कमेटी फैसला करेगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक डॉ. विवेक अग्रवाल की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को 50 से 55 आयु वर्ष के बाद अथवा 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने उपरांत सेवा बढ़ोतरी बारे गठित की गई कमेटी फैसला लेगी। कमेटी के सदस्य के तौर पर अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और संबंधित अनुभाग अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। महानिदेशक की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कमेटी के सदस्य सचिव प्रधानाचार्य से संबंधित केसों की रिपोर्ट प्राप्त करके सफिारिश के लिए हर माह के पहले बुधवार को अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई तिथि को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसके बाद कमेटी फैसला लेगी कि सेवा में बढ़ोतरी की जाए या नहीं।

अभय की सुरक्षा याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई

चंडीगढ़ (जगमार्ग ब्यूरो)। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के बाद ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने जान से मारने की धमकी को लेकर हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है। इससे पहले अभय सात मार्च को अपनी और परिवार के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग राज्य सरकार से कर चुके हैं। अभय ने अपनी याचिका में नफे सिंह राठी हत्याकांड का भी उल्लेख किया है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार चौटाला को मिल रहीं धमकियों और उनकी जान के खतरे का आकलन कर रही है। सरकार ने कोर्ट से इस मामले में जवाब दायर करने के लिए कुछ समय देने की मांग की। सरकार के आग्रह पर जस्टिस विकास बहल ने सरकार को बुधवार तक इस मामले में जवाब दायर करने का समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अपनी याचिका में अभय चौटाला ने हाल ही में कुछ गैंगस्टरों द्वारा इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का भी हवाला दिया। अभय सिंह के मुताबिक 25 फरवरी को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। राठी के शरीर में 11 गोलियां लगी थीं। याचिका के अनुसार लंदन स्थित कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वकील संदीप गोयत के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार अभय हरियाणा राज्य विधानसभा और सार्वजनिक बैठकों और रैलियों में नशीली दवाओं की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वह किसानों और निराश्रितों के समर्थन में भी खुलकर सामने आते रहे हैं और उन्होंने सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का विरोध किया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनकी पद यात्रा के दौरान 17 जुलाई 2023 को रात लगभग नौ बजे कॉल किए गए और वॉयस मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में अभय के निजी सहायक रमेश गोदारा की शिकायत पर हरियाणा पुलिस पहले ही प्राथमिकी दर्जकर चुकी है।

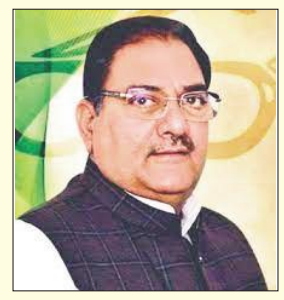

जजपा का लोकसभा चुनाव लड़ने का मंथन अंतिम चरण में

चंडीगढ़ (जगमार्ग ब्यूरो)। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी का मंथन अंतिम चरण में है। अब तक जेजेपी ने सात लोकसभाओं पर चुनाव लड़ने बारे रणनीति बनाई है और बुधवार तक सभी लोकसभा क्षेत्रों पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर ली जाएगी। इसी कड़ी में सोमवार को जेजेपी ने दिल्ली में भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने भिवानी-महेंद्रगढ़ के जेजेपी पदाधिकारियों के सुझाव लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंगलवार को वरिष्ठ जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला सिरसा जिले में सिरसा और हिसार लोकसभा के पदाधिकारियों की राय जानेंगे। वहीं बुधवार को चंडीगढ़ में करनाल लोकसभा के पदाधिकारियों के साथ दुष्यंत चौटाला बैठक करेंगे।

विद्यार्थियों को पूरा स्कॉलरशिप नहीं दे रहे प्राइवेट मेडिकल कालेज

चंडीगढ़ (जगमार्ग ब्यूरो)। हरियाणा में चल रही निजी मेडिकल कालेजों द्वारा इंटर्न और पीजी विद्यार्थियों को पूरी स्कॉलरशिप राशि नहीं दे रहे हैं। इसमें पचास प्रतिशत तक की कटौती की जा रही है। इस संबंध में कुछ विद्यार्थियों द्वारा सीएम विंडो पर शिकायत दिए जाने के बाद चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग निदेशालय ने सभी कालेजों को फटकार लगाते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। इस रिपोर्ट के आधार पर कालेजों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। नियम के मुताबिक स्टूडेंट्स को अधिकतम 91 हजार रुपए स्कॉलरशिप का प्रावधान है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन सिर्फ उन्हें 40 हजार रुपए महीने का ही भुगतान कर रहे हैं। निदेशालय द्वारा एमएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, मुलाना (अंबाला), एसजीटी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बुढेरा (गुरुग्राम),आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, शाहाबाद (कुरुक्षेत्र), अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, धौज, एनसी मेडिकल कॉलेज, इसराना (पानीपत), वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, झज्जर, महर्षि मारकंडेश्वर मेडिकल कॉलेज, सादोपुर (अंबाला) और अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन, फरीदाबाद को स्कॉलरशिप मामले में पत्र जारी करके रिपोर्ट मांगी गई है। डीएमईआर ने मेडिकल कॉलेजों पर अपने इंटर्न और पीजी छात्रों को स्कॉलरशिप के पेमेंट में एनएमसी और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली शिकायतें मिलने पर पत्र जारी किया है। नियमों के अनुसार सरकारी कॉलेज पहले वर्ष के लिए 86,170 रुपए, दूसरे वर्ष के लिए 88,781 रुपए और तीसरे वर्ष के लिए 91,392 रुपए महीने स्कॉलरशिप देने का नियम है। निजी कॉलेज दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार द्वारा नौ अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एमडी-एमएस पाठ्यक्रम की वशेषताओं के बावजूद सभी पीजी छात्रों को सरकार द्वारा पीजी छात्रों को दिए जाने वाले वजीफे के बराबर वजीफा दिया जाएगा।

⇨ निदेशालय ने प्रदेश के आधा दर्जन कालेजों को जारी किया नोटिस

⇨ सीएम विंडो पर आई शिकायत में लगाए आरोप

नियुक्ति

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व एचएसएससी चेयरमैन खदरी से की मुलाकात

कैबिनेट मंत्री कंवरपाल की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी एचएसएससी चेयरमैन

जगमार्ग ब्यूरो

चंडीगढ़। प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सैनी की नियुक्ति के बाद चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का दौर जारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के इस्तीफा देने से नए चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर कवायद शुरू हो गई है। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय हरियाणा कर्मचारी आयोग का नए सिरे से गठन करेगी। 16 मार्च को आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार की तरफ से यह कमेटी गठित की जा चुकी है। इनमें मंत्री के अलावा, मुख्य सचिव और एआर सदस्य के तौर पर शामिल हैं। खास बात ये है कि आचार संहिता से पहले ही सरकार की तरफ से सभी 6 मंडल आयुक्तों से सिफारिशें भी मांग चुके हैं। अब मंडल आयुक्तों के पास जो आवेदन आएंगे, उनमें से सभी मंडल आयुक्त 5-5 लोगों के पैनल सरकार के पास भेजेंगे। इसके बाद कमेटी चेयरमैन समेत 6 नए सदस्यों को लेकर फैसला करेंगे। हालांकि, गठन से पहले सरकार चुनाव आयोग की राय लेगी। इसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। चेयरमैन और सदस्य बनने के लिए भाजपा और आरएसएस संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता जबरदस्त लाबिंग में जुट गए हैं। पुराने मुख्यमंत्री से लेकर नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के यहां हाजिरी शुरू हो गई है। इनके अलावा, कुछ लोग दिल्ली हाईकमान तक अपनी सिफारिश लगा रहे हैं। देखना यह है कि सैनी सरकार ने किसको यह मौका मिलता है।

तीन दिन पहले ही अपने पद से खदरी ने दिया इस्तीफा

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा हो रहा है। चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इस समय आयोग में तीन सदस्य ही शेष हैं। हरियाणा सरकार का भर्तियों को लेकर पूरा जोर है और अभी जेबीटी और ग्रुप सी के 56 और 57 ग्रुप का परिणाम शेष है। इन दोनों भर्तियों में काफी संख्या में पदों पर नियुक्ति होनी है। इसलिए हरियाणा सरकार की मंशा है कि पदों को जल्दी भरा जाए। बकायदा नियुक्तियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो भी जरूरी नियुक्तियां होंगी, उसके लिए यह कमेटी सप्ताह में कम से कम से दो बार बैठक करेगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी सिफारिशें भेजेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल आवश्यकता है तो चुनाव आयोग से अनुमति ली सकती है।

खदरी के घर पहुंचे सीएम सैनी, एक घंटा मंथन

चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके भोपाल सिंह खदरी पंचकूला स्थित आवास पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान आयोग के सदस्य कंवलजीत सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दोनों के साथ भर्तियों और लंबित भर्तियों को लेकर मंथन किया। करीब एक घंटे तक मुख्यमंत्री यहां पर रहे। बता दें कि नायब सैनी और भोपाल सिंह संगठन के समय के दोस्त हैं।